पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय

समक्ष: वी रामास्वामी, यू सिंह, जी मजीठिया, माननीय न्यायमूर्ति

सकटू राम, याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, याचिकाकर्ता

1986 की सिविल रिट याचिका सं 264

5 मई 1988.

पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम (1953 का चतुर्थ)-धारा 102-सर्पकंच के खिलाफ शिकायत-प्रारंभिक जांच के आदेश-निलंबन

जांच के दौरान सरपंच का-निलंबन के आदेश को रद्द करना-शिकायतकर्ता को नोटिस-ऐसे नोटिस की आवश्यकता।

अभिनिर्धारित किया गया कि निलंबन की शक्ति निदेशक में निहित है जिसका प्रयोग केवल अपनी इच्छा से किया जा सकता है, शिकायत के आधार पर जांच शुरू होने पर शिकायतकर्ता तस्वीर में नहीं आता है। शिकायत निदेशक के लिए एक सूचना है। भले ही जांच करने का कोई आधार या आधार हो और यदि वे आधार सत्य पाए जाते हैं, तो आरोपी-अधिकारी को पद से हटाया जा सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि निदेशक जांच लंबित रहने तक निलंबन की अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। उन्हें इस बात से भी संतुष्ट होना होगा कि उनकी राय में लंबित जांच के लिए निलंबन आवश्यक था। निलंबन का सवाल पूरी तरह से निदेशक में निहित विवेकाधिकार है और यह नहीं कहा जा सकता कि किसी के पास निलंबन का आदेश प्राप्त करने का कानूनी या निहित अधिकार है। यदि शिकायतकर्ता के पास निदेशक द्वारा दिए गए आदेश का कोई कानूनी या निहित अधिकार नहीं है, तो निलंबन के आदेश को रद्द करने से पहले उसे कोई नोटिस जारी करने का कोई सवाल ही नहीं है। निलंबन का

मूल आदेश देने के चरण में और निलंबन के आदेश को रद्द करने के चरण में, पहले चरण में आरोपी-अधिकारी या दूसरे चरण में शिकायतकर्ता को कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है।

(पैरा 3, 4 और 7).

यह मामला 1 अप्रैल, 1986 को माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री प्रेम चंद जैन और माननीय श्री न्यायमूर्ति सुखदेव सिंह कांग की खंडपीठ द्वारा पूर्ण पीठ को भेजा गया था, यह प्रश्न सी.डब्ल्यू.पी. में शामिल था। क्या निलंबन आदेश रद्द करने से पहले शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए या नहीं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि पंचायत निदेशक, हरियाणा का आदेश दिनांक 14 अगस्त, 1985 (अनुलग्नक पी. 2) और आयुक्त का आदेश दिनांक 23 दिसंबर, 1985 (अनुलग्नक "पी) -4"), कृपया रद्द किया जाए और याचिका के निपटारे तक इसके संचालन पर रोक लगाई जाए।

याचिकाकर्ता के वकील जी.एस. संधू।

एन.एस.पवार, वरिष्ठ डी.ए.जी. हरियाणा, उत्तरदाताओं के लिए।

एम. एल. सरीन, वरिष्ठ वकील, ए. एस. ग्रेवाल, मिस जयश्री ठाकुर और मिस रितु बाहरी, प्रतिवादी नंबर 3 के लिए वकील हैं।

निर्णय

वी. रामास्वामी, मुख्य न्यायाधीश ।

1. इस रिट याचिका को इस आधार पर पूर्ण पीठ द्वारा विचार करने के लिए भेजा गया है कि सुरेश चंद बनाम पंचायत निदेशक, हरियाणा , 1979 पुन एलजे 116 और राम सरूप बनाम पंचायत निदेशक में दो विरोधाभासी डिवीजन बेंच के फैसले सामने आए हैं। , हरियाणा, 1983 पन एलजे 350 इस सवाल पर कि क्या पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1953 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 102 के तहत किए गए निलंबन के आदेश को रद्द करने से पहले एक शिकायतकर्ता को सुनवाई का

अवसर दिया जाना चाहिए, जैसा कि लागू है हरियाणा राज्य. इससे पहले कि हम उस वास्तविक प्रश्न पर जाएं जिसका उल्लेख किया गया है, हम कुछ तथ्यों पर ध्यान दे सकते हैं जो रिट याचिका दायर करने से संबंधित हैं।

2. तीसरा प्रतिवादी मुख राम ग्राम पंचायत, कैल, पीओ जगाधरी, जिला अंबाला का सरपंच है। इस आधार पर कि उसने अनाधिकृत रूप से ग्राम पंचायत की भूमि पर कब्जा कर लिया है, याचिकाकर्ता ने पंचायत निदेशक, हरियाणा को सरपंच के खिलाफ शिकायत की। उप निदेशक पंचायत, हरियाणा द्वारा प्रारंभिक जांच की गई और जुलाई आईएस, 1985 की अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में उन्होंने माना कि कुछ आरोपों के लिए सरपंच को दोषी ठहराने के लिए प्रथम दृष्टया आधार थे और नियमित जांच का आदेश दिया जा सकता है। 19 जुलाई 1985 को उपनिदेशक की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए निदेशक ने ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 102 के तहत जांच के आदेश दिए और उपमंडल अधिकारी, नारायणगढ़ को जांच अधिकारी नियुक्त किया। उसी दिन, जांच लंबित रहने तक, उन्होंने तीसरे प्रतिवादी को इस आधार पर निलंबित कर दिया कि उसके खिलाफ आरोप इतने गंभीर प्रकृति के हैं कि यदि यह साबित हो गया, तो उसे सरपंच के पद से हटाया जा सकता है और उसे इस पद से रोका जा सकता है। अगले आदेश तक ग्राम पंचायत की किसी भी कार्यवाही में भाग लेना आवश्यक था। जांच पूरी होने से पहले ही, 14 अगस्त, 1985 को निदेशक ने निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया और सरपंच को उसके खिलाफ लंबित जांच पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तुरंत बहाल कर दिया। 14 अगस्त 1985 के निदेशक के इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 102(5) के तहत आयुक्त के समक्ष अपील दायर की। हालाँकि आयुक्त ने मूल रूप से निलंबन के रद्द करने के आदेश पर अपील लंबित रहने तक रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपील को ही खारिज कर दिया और स्थगन आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि निदेशक के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह निलंबन का आदेश जारी करने से पहले याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करता। निलंबन के बाद, याचिकाकर्ता ने 14 अगस्त, 1985 के निरसन आदेश को रद्द करने के लिए यह रिट याचिका दायर की, जैसा कि 23 दिसंबर, 1985 को अपील में आयुक्त के आदेश द्वारा विभिन्न आधारों पर पुष्टि की गई थी।

3. रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए बिंदुओं में से एक यह था कि निलंबन के आदेश को रद्द करने से पहले निदेशक को नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। इस संबंध में, उन्होंने सुरेश चंद के मामले, (1979 पुन एलजे 116)(सुप्रा) में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया। हालाँकि यह निर्णय 22 नवंबर, 1978 का है, लेकिन डिवीजन बेंच ने इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाते हुए, 1 फरवरी, 1977 के पहले डिवीजन बेंच के फैसले पर ध्यान नहीं दिया था। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उस समय इसकी सूचना नहीं दी गई थी। फरवरी 1. 1977 के पहले डिवीजन बेंच के फैसले को राम सरूप के मामले में रिपोर्ट किया गया है। (1983 पुन एलजे 350)(सुप्रा)। इससे पहले कि हम उस निर्णय और प्राधिकारियों पर विचार करें, हरियाणा राज्य पर लागू अधिनियम में प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक है। धारा 102, जो प्रासंगिक प्रावधान है, इस प्रकार है:

"102. पंचों का निलंबन एवं निष्कासन :

(1) निदेशक किसी भी पंच को निलंबित कर सकता है, जहां उसके खिलाफ किसी आपराधिक अपराध के संबंध में जांच, जांच या परीक्षण के तहत मामला दर्ज किया गया हो, यदि निदेशक की राय में, उसके खिलाफ लगाए गए आरोप या की गई कार्यवाही से उसे शर्मिंदा होने की संभावना हो। अपने कर्तव्यों के निर्वहन में नैतिक अधमता या चरित्र दोष शामिल है।

(1ए) निदेशक (या उपायुक्त) किसी जांच के दौरान किसी भी कारण से किसी पंच को निलंबित कर सकता है जिसके लिए उसे हटाया जा सकता है (1-बी) इस धारा के तहत निलंबित कोई पंच किसी भी कार्य में भाग नहीं लेगा निलंबन की अवधि के दौरान पंचायत के कार्य या कार्यवाही और पंचायत के रिकॉर्ड, धन या किसी अन्य संपत्ति को उसके कब्जे में या उसके नियंत्रण में पंचायत में बहुमत का आदेश देने वाले पंच द्वारा अधिकृत व्यक्ति को सौंप देगा।

(2) निदेशक कर सकते हैं। ऐसी जांच के बाद, जैसा वह उचित समझे, किसी भी पंच को हटा दें:--

(ए) धारा 5 की उपधारा (5) में उल्लिखित किसी भी आधार पर;

(बी) जिसने कार्य करने से इनकार कर दिया, या कार्य करने में असमर्थ हो गया। या दिवालिया घोषित कर दिया गया है;

(सी) जो, उचित कारण के बिना, ग्राम पंचायत, या अदालती पंचायत, जैसा भी मामला हो, की बैठकों से लगातार दो महीने से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है;

(डी) जो निदेशक की राय में अपने पिछले या वर्तमान कार्यकाल के दौरान कर्तव्यों के निर्वहन में कदाचार का दोषी रहा हो।

(ई) जिसका पद पर बने रहना निदेशक की राय में जनता के हित में अवांछनीय है।

स्पष्टीकरण--खंड (डी) में 'कदाचार' शब्द में पर्याप्त कारण के बिना सरपंच की विफलता भी शामिल है--

(i) ऐसा करने के लिए किसी भी न्यायालय के आदेश की प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर मामले की न्यायिक फ़ाइल प्रस्तुत करना;

(ii) उसके द्वारा तय किए गए किसी प्रशासनिक या न्यायिक मामले में ग्राम पंचायत के आदेश की एक प्रति, उसके लिए वैध आवेदन प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर प्रदान करना।

(3) एक व्यक्ति जिसे उप-धारा (2) के खंड (ए) या (सी) के तहत हटा दिया गया है, उसे निदेशक द्वारा तय की गई पांच साल से अधिक की अवधि के लिए पुन: चुनाव के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।

(4) एक व्यक्ति जिसे उप-धारा (2) के खंड (बी), (डी) या (ई) के तहत हटा दिया गया है, उसे हटाए जाने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए पुन: चुनाव के लिए अयोग्य माना जाएगा। जिस व्यक्ति को सितंबर 1965 के पहले दिन या उसके बाद उक्त खंडों में से किसी के तहत हटा दिया गया था, वह पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1971 के प्रारंभ होने के बाद ऐसी अवधि के दौरान पुन: चुनाव के लिए अयोग्य माना जाएगा, जो कि अवधि के भीतर आता है। तारीख से पांच साल.

(5) इस धारा के तहत पारित किसी भी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, आदेश की सूचना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, सरकार से अपील कर सकता है।

अधिनियम की धारा 5(5), धारा 102 के खंड (2) में संदर्भित है, जो सरपंच या पंच के रूप में चुनाव में खड़े होने या बने रहने के लिए अयोग्यता से संबंधित है। निलंबन का वर्तमान मामला मूल रूप से एस. 102, खंड (1ए) के तहत एक था, जैसा कि ऊपर निकाला गया है, यह दर्शाता है कि यह एक जांच के दौरान एक पंच को निलंबित करने की निदेशक और उपायुक्त की शक्ति से संबंधित है। सामान्य खंड अधिनियम के तहत , यदि कोई आदेश देने की शक्ति किसी प्राधिकारी में निहित है, तो इसका तात्पर्य किसी भी बाद के चरण में उस आदेश को रद्द करने, संशोधित करने या बदलने की शक्ति भी है, जब तक कि कोई विशिष्ट रोक न हो। यह पार्टियों का मामला नहीं है कि निदेशक के पास कोई शक्ति नहीं है या निलंबन आदेश को रद्द करने के लिए किसी भी प्रावधान के तहत कोई रोक थी। चूंकि उक्त प्रावधान जांच के दौरान प्रयोग की जाने वाली शक्ति को संदर्भित करता है, इसलिए यदि प्रारंभिक जांच में निदेशक का मानना है कि नियमित जांच करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला है, तो उसके द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह हमेशा आवश्यक नहीं है कि उस धारा के उप-खंड (2) के तहत जांच शुरू करने या ऐसी जांच के दौरान सरपंच या पंच को निलंबित करने के लिए शिकायत की जाए। हालाँकि आम तौर पर जब कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो प्रारंभिक जांच यह तय करने के लिए की जाती है कि नियमित जांच का आदेश दिया जाए या नहीं और ऐसी नियमित जांच के दौरान यदि निदेशक संतुष्ट हो जाता है कि आरोप ऐसे हैं, तो अंततः पंच दोषी पाया जाता है। दोषी पाए जाने पर उसे पद से हटाया जा सकता है, वह जांच लंबित रहने तक पंच को निलंबित कर सकता है। यानी, चाहे शिकायत के आधार पर या स्वत: संज्ञान जांच के आधार पर, निदेशक को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या उसे जांच लंबित रहने तक पंच या सरपंच को निलंबित करना होगा। निलंबन स्वत: जांच के आदेश का पालन नहीं करेगा। जांच के दौरान अधिनियम के तहत कार्य करने से रोकने और पंचायत की कार्यवाही में भाग न लेने की आवश्यकता के बारे में प्रत्यक्ष को संतुष्ट होना होगा। इस सवाल पर उन्हें संतुष्ट होना पड़ेगा. यह उनकी राय है जो प्रासंगिक कारक है। बेशक निर्णय मनमाना, मनमौजी या बाहरी विचारों या दुर्भावनापूर्ण नहीं हो सकता। अब हम आदेश की प्रकृति के प्रश्न से भी चिंतित नहीं हैं। लेकिन प्रासंगिक बात यह है कि उस स्तर पर, वह अपनी राय का प्रयोग करते हैं और संबंधित अधिकारी को नोटिस दिए बिना भी

अधिकारी को निलंबित कर देते हैं। जांच के दौरान निलंबन के लिए पंच को निलंबन से पहले नोटिस की आवश्यकता नहीं होती है। इस न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला से अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि निलंबन का आदेश देने से पहले, राजिंदर सिंह बनाम पंचायत निदेशक, पंजाब के मामले में संबंधित पंच या सरपंच को कोई नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी । 1963) 65 पुन एलआर 1085, नरपत सिंह बनाम हरियाणा राज्य, 1985 पुन एलजे 221 और निर्णय। सुरेश चंद का मामला, (1979 पुन एलजे 116)(सुप्रा) पृष्ठ 122 पर। हम इस पहलू का उल्लेख कर रहे हैं, क्योंकि यदि निलंबन का आदेश पंच या सरपंच के संदर्भ के बिना किसके खिलाफ किया जाता है कार्रवाई की गई है, जिसे हम आरोपी-अधिकारी के रूप में संदर्भित करते हैं, उस आदेश से किसी अन्य व्यक्ति पर कोई निहित अधिकार देने का कोई सवाल ही नहीं है। निलंबन की शक्ति निदेशक में निहित होने के कारण इसका प्रयोग केवल अपनी इच्छा से ही किया जा सकता है, शिकायत के आधार पर जांच शुरू होने पर शिकायतकर्ता सामने ही नहीं आता है। शिकायत निदेशक के लिए एक सूचना है। भले ही जांच करने का कोई आधार या आधार हो और यदि वे आधार सत्य पाए जाते हैं, तो आरोपी-अधिकारी को पद से हटाया जा सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि निदेशक जांच लंबित रहने तक निलंबन की अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। उसे इस बात से भी संतुष्ट होना होगा कि उसकी राय में लंबित जांच के लिए निलंबन आवश्यक था और आरोपी व्यक्ति को पंचायत की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शिकायतकर्ता जांच लंबित रहने तक पंच को निलंबित करने का अधिकार नहीं मांग सकता। जब निलंबन आदेश दिया जाता है तो इसे शिकायतकर्ता को दी गई राहत के रूप में भी नहीं माना जा सकता है।

4. अधिनियम की धारा 102(1) में प्रदत्त निलंबन की शक्ति, इस मामले में, पंच या सरपंच के खिलाफ आपराधिक अपराध के संबंध में जांच, पूछताछ या मुकदमा लंबित है! निलंबन की शक्ति का प्रयोग करने के लिए दो शर्तों को पूरा करना होगा; (1) पंच या सरपंच के खिलाफ किसी आपराधिक अपराध के संबंध में जांच, पूछताछ या मुकदमा लंबित रहेगा और (2) निदेशक की राय में, उसके खिलाफ लगाए गए आरोप या की गई कार्यवाही से उसे आरोपमुक्त करने में शर्मिंदगी होने की संभावना है उसके कर्तव्यों में या नैतिक अधमता या चरित्र दोष शामिल है। जबकि खंड (1ए) उसे "जांच के

दौरान" निलंबित करने में सक्षम बनाता है, जो केवल शिकायत दर्ज करना नहीं है, बल्कि कुछ और है, यानी प्रारंभिक जांच और यह निष्कर्ष कि आचरण में नियमित जांच करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला है धारा 102(1) अधिनियम के तहत , यदि उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है, तो वह अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सकता है, बशर्ते कि वह संतुष्ट हो कि अपराध में नैतिक अधमता या चरित्र का दोष शामिल है या उसके खिलाफ कार्यवाही से उसे शर्मिंदा होने की संभावना है। अपने कर्तव्यों के निर्वहन में. भले ही अपराध में नैतिक अधमता या चरित्र दोष शामिल हो या उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शर्मिंदा होने की संभावना हो, निदेशक के लिए पंच को निलंबित करना अनिवार्य नहीं है। इन दोनों परिस्थितियों में, इसलिए निलंबन का प्रश्न पूरी तरह से निदेशक में निहित विवेकाधिकार है और किसी को भी निलंबन का आदेश प्राप्त करने का कानूनी या निहित अधिकार नहीं कहा जा सकता है। यदि याचिकाकर्ता के पास निदेशक द्वारा दिए गए आदेश का कोई कानूनी या निहित अधिकार नहीं है, तो निलंबन आदेश रद्द करने से पहले उसे नोटिस जारी करने का कोई सवाल ही नहीं है।

5. राम सरूप के मामले (1983 पुन एलजे 350) (सुप्रा) में दिए गए निर्णय में यही विचार लिया गया था। उस मामले में भी, रिट याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा के पंचायत निदेशक के आदेश पर सवाल उठाया, जिसमें शिकायतकर्ता को नोटिस दिए बिना एक पंच के निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया गया था। विद्वान न्यायाधीशों ने कहा:--

"जहां किसी लोक सेवक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी को सूचना दी जाती है और उस सूचना के अनुसरण में कार्रवाई की जाती है, हम नहीं सोचते कि सूचना देने वाले को अवसर देना आवश्यक है। यदि संबंधित प्राधिकारी बाद में इसे रद्द करना चाहता है इसका पूर्व आदेश। मुखबिर एक मात्र मुखबिर से अधिक कुछ नहीं है और उसे लिस का पक्षकार या पीड़ित पक्ष नहीं माना जा सकता है, केवल उस कारण से ताकि लोक सेवक के खिलाफ आदेश को रद्द करने से पहले उसकी बात सुनी जा सके।"

इस परिच्छेद के बाद अगले वाक्य में उल्लिखित सादृश्य बिल्कुल सटीक नहीं हो सकता है, लेकिन नोटिस के प्रश्न पर विद्वान न्यायाधीशों का दृष्टिकोण निश्चित है और सादृश्य द्वारा रंगीन नहीं है।

6. सुरेश चंद के मामले में दूसरे निर्णय में, (1979 पुन एलजे 116)(सुप्रा) राम सरूप के मामले में उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखे बिना, (1983 पुन एलजे 350)(सुप्रा) जो पहले का निर्णय था, हालांकि बाद में रिपोर्ट किया गया, एक अन्य खंडपीठ ने इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है। इस संबंध में जो अनुच्छेद प्रासंगिक है वह पृष्ठ पर है। फैसले का 125 जो इस प्रकार है:--

"इस आदेश को रद्द करने को उचित ठहराने वाला एक और आधार है, यानी, यह याचिकाकर्ता नंबर 1 की शिकायत पर था कि प्रतिवादी नंबर 2 एन. पी. 2 में दर्ज निष्कर्ष पर पहुंचा था। जब प्रतिवादी नंबर। 1 को एन पी 2 से अलग होना था। इसके पारित होने के तुरंत बाद, स्थिति की आवश्यकता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और मांगे राम के मामले (सुप्रा) में निर्धारित सिद्धांतों की आवश्यकता थी कि याचिकाकर्ता नंबर 1 के खिलाफ सुना जाना चाहिए था प्रस्तावित आदेश। इसलिए, आदेश अनु. पी. 3 को उपरोक्त कारणों से रद्द किया जाता है..."

मांगे राम के मामले में संदर्भित निर्णय वही है जो मांगे राम बनाम हरियाणा राज्य (1968) 70 पुन एलआर 307 में बताया गया है। उस निर्णय में, यह मानते हुए कि शिकायतकर्ता के पास निलंबित करने वाले आदेश की वैधता को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। पिछले आदेश का कार्यान्वयन जिसके तहत एक पंचायत समिति के अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया था, ने यह विचार व्यक्त किया कि पंजाब पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम, 1951 में जांच के परिणाम लंबित रहने तक निलंबन के आदेश को रद्द करने या संशोधित करने का कोई प्रावधान नहीं है। हम विद्वान न्यायाधीश के इस दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ हैं क्योंकि जनरल क्लॉज़ एक्ट के तहत । जिसका हमने पहले उल्लेख किया है और जो उस मामले में विवाद में नहीं है, निदेशक के पास जांच के परिणाम आने तक निलंबन के पहले के आदेश को रद्द करने या संशोधित करने की शक्ति है। विद्वान वकील ने ग्राम पंचायत कमालपुर बनाम उप मामले के एक फैसले का भी हवाला दिया। कॉमरेड जिला जींद, (1968) 70 पन एलआर 403। वह एकल पीठ का निर्णय था, लेकिन वह उस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों पर था जहां पंचायत को सरपंच के खिलाफ खड़ा किया गया था और सक्षम प्राधिकारी का मौजूदा आदेश था। सरपंच को अपने कब्जे वाली पंचायत की जमीन पर कब्ज़ा दिलाने और पंचायत के पास कुछ धनराशि जमा करने के लिए, जिसका अनुपालन नहीं

किया गया था और यही वह आधार था जिस पर निलंबन आदेश दिया गया था। में। परिस्थितियों के अनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि बहाली का निर्णय पंचायत के पीछे और पंचायत को उपायुक्त के समक्ष सामग्री रखने का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए था, जिस पर उसका निष्कासन उचित होगा। हमारी राय में, सबसे उचित और उचित दृष्टिकोण वह है जो राम सरूप के मामले (सुप्रा) में व्यक्त किया गया है।

7. हम इस न्यायालय की खंडपीठ के एक अन्य फैसले का भी उल्लेख कर सकते हैं जिसमें हममें से दो (वी. रामास्वामी सीजे और उजागर सिंह जे.) एक पक्ष थे और यह नाथू राम बनाम एसएन गोयल, (1988) में बताया गया है। 1 भूमि एलआर 517. उस मामले में, जांच लंबित रहने तक, सरपंच को निलंबित कर दिया गया था। जांच अधिकारी ने माना कि 1 में से 8 आरोप साबित हुए थे और रिपोर्ट निदेशक को सौंप दी गई थी। निदेशक ने सरपंच को रिपोर्ट भेजकर स्पष्टीकरण मांगा कि क्यों न जांच अधिकारी के निष्कर्ष को स्वीकार किया जाए। सरपंच ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। सरपंच के स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद, निदेशक ने माना कि सभी 11 आरोप साबित नहीं हुए हैं और इस दृष्टि से, निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया और उन्हें सरपंच के रूप में बहाल कर दिया। शिकायतकर्ता ने रिट याचिका दायर कर निदेशक के इस आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की. रिट-याचिकाकर्ता की एक दलील जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, वह यह थी कि निदेशक को जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट शिकायतकर्ता को भी भेजनी चाहिए थी और निलंबन के पिछले आदेश को रद्द करने से पहले उसका स्पष्टीकरण भी मांगना चाहिए था। यह माना गया कि शिकायतकर्ता को कोई नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं था, उसे यह बताने के लिए बुलाया जाए कि क्या रिपोर्ट स्वीकार की जा सकती है और क्या बहाली का आदेश नहीं दिया जा सकता है और निलंबन रद्द क्यों नहीं किया जा सकता है। डिवीजन बेंच ने यह भी माना कि नोटिस न देकर निदेशक द्वारा प्राकृतिक न्याय के किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया गया है। यह निर्णय जांच पूरी होने के बाद निलंबन रद्द करने के मामले के रूप में भी है, क्योंकि विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या आदेश रद्द करने से पहले कोई नोटिस दिया जाना चाहिए, क्या यह प्रासंगिक है और, हमारी राय में, इससे कोई फर्क नहीं

पड़ता, क्योंकि आदेश जारी करने का चरण केवल इस बात पर विचार करने के उद्देश्य से प्रासंगिक होगा कि क्या रद्द करने के लिए कोई सामग्री थी और इस सवाल पर नहीं कि क्या शिकायतकर्ता को कोई नोटिस जारी किया जाएगा। लेन-देन करते समय. प्रश्न के साथ, हमें गुण-दोष या अन्य आधारों जैसे द्वेष आदि के आधार पर आदेश की वैधता को अलग रखना होगा, जो इस प्रश्न से पूरी तरह से अलग है कि क्या निरस्तीकरण का आदेश देने से पहले शिकायतकर्ता को नोटिस दिया जाएगा। यहां तक कि जिस शिकायतकर्ता को नोटिस नहीं दिया गया था, उसे भी इस आधार पर आदेश पर सवाल उठाने का अधिकार हो सकता है कि रद्द करने के लिए कोई सामग्री नहीं है या इस आधार पर कि आदेश दुर्भावनापूर्ण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रद्द करने का आदेश देने से पहले ,शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया जाएगा। दोनों मूल निर्माण के चरण में हैं। निलंबन के आदेश और निलंबन के आदेश को रद्द करने के चरण में, पहले चरण में आरोपी-अधिकारी या दूसरे चरण में शिकायतकर्ता को कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है।

8. उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि सुरेश चंद का मामला, (1979 पुन एलजे 1 16)(सुप्रा), जहां तक यह शिकायतकर्ता को पहले दिए जाने वाले नोटिस या सुनवाई के अवसर के प्रश्न से संबंधित है निलंबन के आदेश को रद्द करना गलत निर्णय है और सही दृष्टिकोण यह है कि राम सरूप के मामले में निर्णय में, (1983 पुन एलजे 350)(सुप्रा)। हम तदनुसार संदर्भ का उत्तर देते हैं।

9. जब हमने आदेश की वैधता से संबंधित अन्य आधारों पर गुण-दोष के आधार पर मामले को निपटाने के लिए मामले को विद्वान एकल न्यायाधीश के पास भेजना चाहा तो उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने बताया कि जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और सरपंच को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपों के लिए दोषी नहीं पाया गया और इसलिए। मामले को विद्वान एकल न्यायाधीश के पास वापस भेजना आवश्यक नहीं हो सकता है और हम रिट याचिका को खारिज कर सकते हैं। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने भी जांच के निष्कर्षों के मद्देनजर मामले में गुण-दोष के आधार पर बहस नहीं की।

10. तदनुसार रिट याचिका विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

11. याचिका खारिज.

* प्रेम चंद जैन सीजे और सुखदेव सिंह कांग, जे., डी/- 1-4-1986 द्वारा दिए गए संदर्भ के आदेश पर पूर्ण पीठ द्वारा निर्णय लिया ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

शिवदेव शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अम्बाला,हरियाणा